

## 21 सितंबर माओवादी पार्टी की दसवीं बरसगांठ को जोरशोर के साथ मनाओ!

# माओवादी जनयुद्ध के ओड़िशा में बढ़ते कदम...

## आईये जनयुद्ध को हर तरह की मदद देते हुए जनता के पक्ष में खड़े हों!

बरस 2004, दिनांक 21 सितंबर, भारत की क्रांति में एक ऐतिहासिक दिन. इस बरस उस दिन को पूरे दस साल हो रहे हैं. एक ऐसा दिन जिसने देश की उत्पीड़ित क्रांतिकारी जनता, क्रांतिकारी ताकतों, प्रगतिशील, जनवाद पसंद बुद्धिजीवियों, क्रांतिकारी आंदोलन का समर्थन कर रही अंतर्राष्ट्रीय क्रांतिकारी ताकतों के दिलों को खुशियों से भर दिया था. और भारत के दलाल नौकरशाह पूंजीपतियों, बड़े-बड़े सामंतों, और साम्राज्यवादी देशों व खासकर अमेरीकी साम्राज्यवाद के दिलों में हड़कंप मचा दिया था. वह दिन था दोस्तो भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माले (पीपुल्सवार) व माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर ऑफ इंडिया (एमसीसीआई) के विलय का दिन! इस विलय के बाद प्रधानमंत्री ने कहा यह 'देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है.'

दरअसल खतरा देश की आंतरीक सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि माओवादी पार्टी के नेतृत्व में चल रहा जनयुद्ध दलाल बड़े पूंजीपतियों, विदेशी कंपनियों और जमींदारों द्वारा जारी लूट को था. देश के शोसक-शासकों को पता था कि दो बड़ी माओवादी पार्टियों के विलय से माओवादी आंदोलन न केवल अखिल भारतीय स्वरूप का आंदोलन बन जायेगा बल्कि उसकी सैनिक ताकत भी बढ़ जायेगी. यही हुआ! माओवादी पार्टी ने अपनी पीएलजीए की मदद से भारतीय क्रांति को ऐतिहासिक रूप से आगे बढ़ाया है. न केवल सैनिक रूप से बल्कि राजनैतिक रूप से भी माओवादी पार्टी भारत की शोषित-उत्पीड़ित जनता के लिए एक विकल्प बनकर उभरी है. दुनिया भर की माओवादी, क्रांतिकारी ताकते भाकपा (माओवादी) की तरफ आशा भरी नजरों से देख रही है.

माओवादी पार्टी खासतौर से देश के सबसे उत्पीड़ित, पिछड़े, सरकारों द्वारा सदियों से उपेक्षित आदिवासी इलाकों में काफी हद तक लूटेरी, विदेशी व बहुराष्ट्रीय कंपनियों की लूट के सामने एक चुनौती पेश कर रही है, एक हद तक उनकी लूट पर अंकुश लगा पाई है. वन विभाग द्वारा किये जाने वाले शोषण-उत्पीड़न, लूट, महिलाओं की इज्जत के साथ खिलवाड़, बेगारी आदि पर रोक लगा पाई है, उसने आदिवासी जनता को सम्मान और इज्जत के साथ जीना सीखाया है, अपने अधिकारों के लिए सशस्त्र होकर लड़ने के लिए प्रेरित किया है, आज देश के आदिवासी अपने जल-जंगल व जमीन के लिए जी-जान से लड़ रहे हैं.

पार्टी विलय के एक साल बाद यानि 2005 में यूपीए सरकार ने एक तरह से देश की जनता के खिलाफ अघोषित युद्ध छेड़ दिया. अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग नामों से चौतरफा सैनिक दमन अभियान चलाया गया. छत्तीसगढ़ में सलवा जुद्ध, झारखंड में नागरिक सुरक्षा समिति, बंगाल में हरमद वाहिनी आदि. माओवादी पार्टी के निर्मूलन के लिए केंद्रीय स्तर पर अभूतपूर्व प्रयास तेज हो गए.

सलवा जुद्ध सैनिक फासीवादी अभियान ने बस्तर में 600 से ज्यादा गांवों को जला कर राख कर दिया, सैकड़ों महिलाओं के साथ सरकारी सशस्त्र बलों, विशेष पुलिस अधिकाइयों (एसपीओ) ने सामूहिक बलात्कार किये, फसलों को तबाह कर दिया, और हजार से ज्यादा लोगों को मार डाला. लेकिन बस्तर की आदिवासी जनता ने, हमारी पार्टी के नेतृत्व में, और प्रगतिशील, जनवादी बुद्धिजीवियों, मानव अधिकार कार्यकर्ताओं के समर्थन से इस फासीवादी दमन अभियान को नाकों चने चबवाए. विश्वस्तर पर माओवादी जनयुद्ध को समर्थन प्राप्त हुआ. पीएलजीए ने लड़ते हुए युद्ध को सीखा और दुश्मन के फासीवादी बलों को करारे सबक सिखाए. हजारों की संख्या में जन मिलिशिया का गठन हुआ, सैकड़ों मिलिशिया सदस्य पीएलजीए में भर्ती हुए और देश की मुक्ति की लड़ाई में कूद पड़े. दंडकारण्य में इस क्रूर दमन का सामना करते हुए जनता ने ग्राम स्तर से लेकर जिला स्तर तक अपनी जनताना सरकारों का निर्माण किया. आज जोन स्तरीय जनताना सरकार बनाने की तरफ दंडकारण्य की जनता आगे बढ़ रही है.

क्रांतिकारी जन कमेटी (जनताना सरकार) अपने कृषि विभाग के जरिये हजारों एकड़ जमीन को खेती योग्य बनाने में कामयाब हुई है. लाखों महिला-पुरुषों, बच्चों, बुर्जुगों और जनमिलिशिया, पीएलजीए की मदद से यह संभव हो सका है. उसने अपने शिक्षा विभाग के तहत स्कूलों का संचालन शुरू किया है जिसमें सैकड़ों बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं. जनताना सरकार के अपने स्वास्थ्य विभाग है जिसके जन डॉक्टर हजारों जनता तक निशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचा रहे हैं. जनताना सरकारों के नेतृत्व में सहकारी आंदोलन आगे बढ़ रहा है. न्यायीक विभाग बिना देरी किये, जनता से ही न्यायधिस चुन कर फैसले सुना रहा है, बिना देरी व बिना खर्च जनवादी फैसले जनता को मिल रहे हैं. इन जनताना सरकारों के संचालन में उनकी सुरक्षा करते हुए जन मिलिशिया अहम योगदान निभा रहा है. जनताना सरकारों का सुरक्षा विभाग इसका संचालन करता है.

सलवा जुद्ध की करारी हार के बाद तिलमिलाए शोषक-शासक वर्गों ने कोबरा फोर्स का गठन करके और भी क्रूर और फासीवादी ऑपरेशन ग्रीनहंट अभियान की शुरुआत की. यह क्रूर अभियान आज भी जारी है. लेकिन हमारी पीएलजीए और क्रांतिकारी जनता इसका डटकर मुकाबला करते हुए आगे बढ़ रही है.

इस दौरान जनता का दमन करने वाले फासीवादी बलों का पीएलजीए ने जनता की मदद से बहादुरी पूर्ण मुकाबला किया और उस पर कई ऐतिहासिक हमले किये. दंडकारण्य में रानीबोदली, उरपलमेड़ा, लाहेरी, टव्वेटोला, मदनवेड़ा, कोंगेरा, ताड़मेटला, मुकरम, ओड़िशा में नयागढ़, बालिमेल्ला, कलिमेल्ला, बिहार-झारखंड में लखिसराय, सारंडा, गिरडिह, पश्चिम बंगाल में सिलदा रेड आदि प्रमुख है. सैकड़ों दुश्मनों का सफाया कर सैकड़ों हथियार पीएलजीए ने जब्त किये हैं. वहीं जहानबाद, लखिसराय, दंतेवाड़ा आदि जेल ब्रेक कर कई वरिष्ठ नेताओं, कार्यकर्ताओं व सैकड़ों निर्दोष जनता को छुड़वाने में हमारी पार्टी कामयाब हुई है.

इन दस सालों में हमारी पार्टी ने कई ऐतिहासिक जन आंदोलनों को खड़ा किया है, उनमें भागीदारी की है. जनता के हर जायज आंदोलन के साथ हमारी पार्टी खड़ी रही है.

पश्चिम बंगाल के सिंगुर में टाटा बहुराष्ट्रीय कंपनी को भागना पड़ा, नंदीग्राम से इंडोनेशिया के सलेम ग्रुप को अपना बोरिया बिस्तर समेटना पड़ा और लालगढ़ इलाके से बड़े व दलाल पूंजीपति जिंदाल को उलटे पांव लौटना पड़ा. इतना ही नहीं 30 सालों से जड़ जमा कर बैठे सामाजिक फासीवादी नकली मार्क्सवादियों के शासन को भी जनता ने उखाड़ फेंका. अमर शहीद, भारतीय क्रांति के प्यारे नेता कामरेड किशनजी की रहनुमाई में लालगढ़ की जनता ने नक्सलबाड़ी विद्रोह की याद ताजा कर दी. इस ऐतिहासिक विद्रोह को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जनता का समर्थन प्राप्त हुआ. केंद्र व राज्य सरकारों की नींद हराम कर दी गयी.

ओड़िशा में पीछले दस सालों में माओवादी आंदोलन बालको, नालको, वेदांता, पोस्को, टाटा, मित्तल, जिंदल आदि बहुराष्ट्रीय कंपनियों व खदान माफियाओं के लिए लाल भूत बनकर खड़ा हुआ है. माओवादी पार्टी के समर्थन व नेतृत्व में ओड़िशा की जनता खासकर आदिवासी जनता विस्थापन व शोषण के खिलाफ उठ खड़ी हुई है. खासतौर से बॉक्सआईट के अंतर्राष्ट्रीय माफियाओं से जनता टक्कर ले रही है. नियमगिरी, गंदमर्दान पहाड़ों को अपना देवता मानकर जनता उनकी रक्षा के लिए जीवन मरण का संघर्ष कर रही है. कलिंगनगर में टाटा, जगतसिंगपुर में पोस्को, लांजीगढ़-नियमगिरी में वेदांता के खिलाफ जनता निर्णायक लड़ाई लड़ रही है.

नारायणपटना के आदिवासियों की लड़ाई ने फिर एक बार जमीन जोतने वाले व सामंती शोषण को भारतीय राजनीति के पटल पर रखा. संशोधनवादी पार्टियों के अवसरवादी नेतृत्व से मुक्ति पाकर जनता ने साहूकारों, जमींदारों, सूदखोरों व शराब माफियों के खिलाफ ऐतिहासिक आंदोलन छेड़ा और विजय हासिल की.

दो महाधाराओं के विलय के बाद 2007 में संपन्न ही एकता कांग्रेस-नौवीं कांग्रेस के दिशा-निर्देशों के अनुसार माओवादी पार्टी ने अपने आंदोलन का विस्तार किया. देश के दो प्रधान जोन डीके और बिहार-झारखंड के बीच के इलाके यानि ओड़िशा को इस विस्तार के लिए महत्वपूर्ण माना गया. आज ओड़िशा राज्य कमेटी इस महत्वपूर्ण कार्यभार को लेकर आंदोलन को आगे बढ़ा रही है.

छत्तीसगढ़ के रायपुर जिला के मैनपुर ब्लॉक से इस विस्तार की शुरुआत हुई. अब वह इलाका गरियाबंद जिला में आता है. सबसे पहले मैनपुर डिवीजन का गठन हुआ. डीकेएसजेडसी के नेतृत्व में यहां आंदोलन के विस्तार की शुरुआत हुई थी. 2007 में एक प्लाटून की संख्या हमारी पार्टी मैनपुर ब्लॉक के सीतानदी एरिया में कदम रखी. जनता ने दिल खोल कर स्वागत किया जैसे वह बरसों से हमारे आंदोलन का इंतजार कर रही हो. जहां भी दस्ता जाता लोग स्वागत के लिए खड़े होते, लाल सलाम करते और अपनी समस्याएं सामने रखते. जनता जंगल-पहाड़ों में पार्टी को देखने के लिए आती थी. क्योंकि यह इलाका सितानदी-उदंती वन अभ्यारण्य में आता था. वहीं ओड़िशा के नुआपाड़ा जिला का सोनाबेड़ा इलाका भी एक वन अभ्यारण्य है. ये दोनों सटे हुए हैं. इस प्रकार सीतानदी, उदंती, सोनाबेड़ा की आदिवासी जनता सालों से इन वन अभ्यारण्यों के खिलाफ लड़ रही थी. वन विभाग इनका मनमाना शोषण करता था. वनों से लकड़ी लाना, तेंदुपत्ता तोड़ना, गाय-भैंस चराना, वनोपजों का संग्रहण करना आदि सब मना था. कोई खेती के लिए जमीन नहीं काट सकता था. अगर ऐसा कोई करता तो वन विभाग केस लगा कर जेल भेज देता था. जनता कोर्ट की तरीख पर तारीख के चक्कर में पड़ कर कंगाल बन जाती थी. मजबूरीवश वन विभाग के गार्ड से लेकर डीएफओ तक को रिश्वत देनी पड़ती थी. जनता इन सब से बहुत तरस्त थी. जैसे ही पार्टी ने कदम रखे फारेस्ट डिपार्टमेंट अपनी वर्दियों को लगाना छोड़ दिया और अपना बोरिया बिस्तर समेट लिया. बरसों से संघर्ष कर रहे और लूट रहे लोगों को बहुत चैन मिला. उनका सबसे बड़ा दुख दूर हो गया. इस प्रकार पार्टी को जनता 'भगवान' की तरह देखती व दूर दूर से अपने गांव में आने का न्यौता भेजती थी.

वन विभाग के भागने से हजारों भूमिहीन किसानों, बड़ी संख्या में गरीब किसानों को भी जमीने मिलीं. लगभग सभी गांवों से भूमिहीनता की समस्या तो दूर हुई है. इसी तरह लघु वनोपजों के संग्रहण की अनुमति देने, तेंदुपत्ता तोड़वाई की मजदूरी बढ़वाने के लिए भी हजारों जनता जन आंदोलनों में गोलबंद हुई. तेंदुपत्ता तुड़वाई की मजदूरी बढ़वाने के लिए 2012 में नुआपाड़ा जिला मुख्यालय पर 3000 के आसपास लोगों ने रैली की. वनोपज के दाम बढ़वाने के लिए तुरेकेला में 5000 से ज्यादा लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया. जनता ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और बंद का आह्वान दिया, जो सफल रहा. भावसिल, कटिनपानी आदि गांवों में साहूकारों, बड़े व्यापारियों व जमींदारों की जमीनों को जनता ने जब्त किया. सूदखोरों के यहां गिरवी जमीन वापिस ली गयी.

पार्टी का प्रभाव दूर-दूर तक फैला. इसको देख कर 2010 में मैनपुर डिवीजन से फिर आंदोलन विस्तार हुआ. पार्टी के नेतृत्व में बरगढ़, बलांगिर, महासमुंद तक विस्तार किया. इस विस्तार के दौरान हमारे कई प्रिय कामरेड शहीद हुए. लेकिन आज उनकी बंदोबस्त हमारी पार्टी बरगढ़-बलिंगर-महासमुंद डिवीजनल कमेटी का गठन कर जनता को क्रांतिकारी आंदोलन में गोलबंद कर पा रही है. उस इलाके में जमींदारों के खिलाफ जनता उठ खड़ी हुई है. सामंती शोषण को चुनौती दे रही है.

हमारी पार्टी के नेतृत्व में जनता के जारी संघर्ष से घबरा उठी विदेशी कंपनियों, बहुराष्ट्रीय कंपनियों और जमींदारों की लूट को जारी रखने के लिए माओवादी आंदोलन को कुचलने के लिए ऑपरेशन ग्रीनहंट चलाया जा रहा है. हम कहते हैं हमारा आंदोलन जनता का जायज व न्यायीक युद्ध है. जबकि लूटेरे शासक वर्ग जो जनता पर लाखों सशस्त्र बलों को उतार रहे हैं, हवाई हमलों की तैयारी कर रहे हैं वह पूंजीपति व जमींदारों के फायदे के लिए किया जाने वाला नजायज व अन्यायपूर्ण युद्ध है. यह युद्ध उन तमाम लोगों के खिलाफ है जो विस्थापन-बेरोजगारी, गरीबा-भूखमरी, और अपने जल-जंगल-जमीन के लिए लड़ रहे हैं.

दोस्तो युद्ध जारी है, टाई और लंगोटियों के बीच, झोपड़ी और कोठियों के बीच, आपको तय करना है आप किसके पक्ष में हो, आदमखोरों की ओर हो या आदमी की ओर हो! हमारा लक्ष्य सीधा है, देश को आजाद करवाने के लिए, सबके लिए रोटी, कपड़ा और मकान के लिए, हर हाथ को काम हर व्यक्ति को सम्मान के लिए, आदिवासी, दलित जनता के विकास के लिए, महिला-पुरुषों की समानता के लिए बड़े दलाल पूंजीपतियों, जमींदारों, साम्राज्यवादियों को उखाड़ फेंकना है. इसके लिए मजदूर, किसान, छोटे व्यापारी, दुकानदार, कर्मचारी, छात्र, अल्पसंख्यक, राष्ट्रीय पूंजीपति सब हमारे दोस्त हैं. आईये मिलकर एक नवजनवादी भारत के सपने को साकार करें. आईये माओवादी जनयुद्ध को हर तरह की मदद देते हुए जनता के पक्ष में खड़े हों!

**ओड़िशा राज्य कमेटी भाकपा (माओवादी)**